RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

हैलो सरकार

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

वर्ष-25 | अंक-257 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, गुरूवार 21 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दु:ख होता है।

–चाणक्य

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

राजस्थान के हर जिले में बनेंगे डिजिटल मॉडल अस्पताल

जयपुर। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक राजकीय और निजी अस्पताल को मॉडल फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन अस्पतालों में आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो सकेगा।

अब मरीजों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जयपुर स्थित सीफू में एबीडीएम मॉडल फैसिलिटी इनिशिएटिव के तहत चयनित निजी अस्पतालों के लिए राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रक्रियाओं, तकनीकी व्यवस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की विस्तृत जानकारी देना था।

एबीडीएम के तहत मरीजों की बनेगी आभा आईडी

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने बताया कि एबीडीएम के तहत मरीजों की आभा आईडी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से उनका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। इससे मरीजों को बार-बार दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डॉक्टरों को भी उपचार में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और निर्धारित आईडी के जरिए आवश्यक सूचनाएं अपलोड करनी होंगी।

बिना परमिशन एक भी जहाज नहीं निकलने देंगे-ईरान

हमें हॉर्मुज को खोलना ही होगा-ट्रंप

ईरान ने कुछ ही देर पहले खुलकर यह कह दिया है कि बिना अनुमति के वह किसी भी टैंकर या जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है। उन्होंने भी साफ कहा है कि हॉर्मुज अब किसी भी तरह से खोलना ही होगा।

बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है। इस बीच, पाकिस्तान दोनों के बीच शांति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश में जुटा है।

ईरान नेवी ने क्या कहा?

ईरान की नेवी ने हॉर्मुज को लेकर बयान जारी करते हुए कहा- पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट से 26 जहाज गुजरे हैं। उसने यह भी साफ़ कर दिया है कि इस स्ट्रेट से होने वाला यातायात फिलहाल एक परमिट प्रणाली के तहत संचालित हो रहा है।

उधर, ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा- हमें हॉर्मुज को खोलना होगा। हम इसके लिए एक कोशिश करेंगे। हालांकि, हमें इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। यह बयान संकेत देते हैं कि दोनों पक्ष शर्तों के हिसाब से समझौता करने को तैयार हैं।

ईरान नेवी ने जारी किया फुटेज

इस बीच, ईरानी नेवी ने एक ड्रोन द्वारा हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर हमला करने का फुटेज जारी किया है। आरोप है कि यह जहाज बिना भुगतान किए वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था।

बता दें कि हॉर्मुज में वसूली को लेकर कई देश विरोध कर रहे हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से यह भी सफाई सामने आई थी कि वह समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर कोई टैक्स नहीं ले रहा है। वहीं, ताजा वसूली के मामले ने सबको चौंका दिया है।

खाद्य संकट की चेतावनी

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने भी दुनिया भर को गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा, यह भी खबर सामने आई है कि नाटो इस बात पर चर्चा कर रहा है कि यदि जुलाई की शुरुआत तक हॉर्मुज फिर से नहीं खुलता है, तो वहां सैनिक तैनात किए जाएं। जिससे तनाव और बढ़ने की उम्मीद है।

सरस डेयरी ने दूध के 2 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ाए

जयपुर। महंगाई की मार झेल रहे आमजन को अब दूध के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। जयपुर डेयरी ने सरस दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 21 मई की शाम से लागू होंगी। इसके साथ ही दही, छाछ और लस्सी जैसे दुग्ध उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से जारी नई दरों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को सरस दूध के अलग-अलग वैरिएंट के लिए पहले से अधिक भुगतान करना होगा।

डेयरी प्रशासन का कहना है कि बढ़ती लागत और संचालन खर्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि उपभोक्ताओं के बीच इस निर्णय को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। नई दरों के अनुसार सरस टोंड दूध, जिसे नीले पैकेट में बेचा जाता है, अब 54 रुपए की जगह 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।

इसी तरह स्टैंडर्ड दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। सरस गोल्ड दूध अब 68 रुपए के बजाय 70 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डबल टोंड दूध की कीमत बढ़कर 48 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी।

घरेलू बजट पर असर पड़ना तय

डेयरी ने केवल दूध ही नहीं, बल्कि उससे तैयार होने वाले अन्य उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा किया है। नई कीमतें 21 मई की शाम से सप्लाई होने वाले सभी उत्पादों पर लागू रहेंगी। इससे रोजाना सरस उत्पाद खरीदने वाले हजारों उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि डेयरी को आमजन को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए था।

पहले भी बढ़ चुकी कीमत

इससे पहले भी जयपुर डेयरी अगस्त 2025 और अगस्त 2024 में दूध के दाम बढ़ा चुकी है। दोनों बार प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वर्ष 2017 से अब तक दूध की कीमतों में 12 बार इजाफा हो चुका है। दूध के बढ़े हुए दामों का असर जयपुर और दौसा जिले के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

जयपुर डेयरी इन दोनों जिलों में प्रतिदिन करीब 11.60 लाख लीटर दूध की सप्लाई करती है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की गई थी।यार होने वाले अन्य उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा किया है। नई कीमतें 21 मई की शाम से सप्लाई होने वाले सभी उत्पादों पर लागू रहेंगी। इससे रोजाना सरस उत्पाद खरीदने वाले हजारों उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि डेयरी को आमजन को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए था।

जयपुर में शीघ्र शुरू होगी सहकारी मॉडल पर आधारित 'भारत टैक्सी' सेवा-गौतम कुमार दक

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शीघ्र ही जयपुर में भी शुभारंभ होगा। यह सेवा आमजन को किफायती और सुरक्षित परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही, 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करते हुए सारथियों (चालकों) की आर्थिक उन्नति का आधार भी बनेगी। सहकारिता मंत्री बुधवार को अपेक्स बैंक सभागार में भारत टैक्सी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सारथियों (चालकों) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली, लखनऊ, मुम्बई और चण्डीगढ़ के बाद अब जयपुर सहित अन्य शहरों में शीघ्र भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। जयपुर में जून माह के प्रथम सप्ताह में इस सेवा की शुरूआत प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी एक ऐसी अनूठी सेवा है, जिसमें मालिक कोई बाहरी व्यक्ति या कम्पनी नहीं होकर स्वयं टैक्सी चलाने वाले सारथी हैं। यह सेवा स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण के चार मूल विचारों पर आधारित है। इसमें टैक्सी चलाने वाला सारथी ही कंपनी का वास्तविक मालिक होगा। दक ने कहा कि भारत टैक्सी में किसी भी सारथी का अकाउंट बिना सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। भारत टैक्सी से सारथियों को हिडन चार्जेज से भी मुक्ति मिलेगी। सारथियों को विकल्प उपलब्ध होने से निजी कम्पनियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। इस प्रकार, सहकार टैक्सी सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। सहकारिता मंत्री ने सारथियों से आह्वान किया कि वे अन्य चालकों को भी इसके फायदों की जानकारी देकर अधिक से अधिक संख्या में उन्हें भारत टैक्सी के साथ जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर सारथियों ने अपने अनुभव एवं सुझाव साझा करते हुए कहा कि वे भारत टैक्सी की शुरूआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी कम्पनियों के साथ कार्य करने में उन्हें विभिन्न प्रकार से शोषण का सामना करना पड़ता है और उनकी आमदनी में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। सारथियों ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि भारत टैक्सी स्वदेशी सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होगी, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी की शुरूआत से उन्हें निजी कम्पनियों के मनमाने सब्सक्रिप्शन चार्जेज से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे भारत टैक्सी के संचालन में राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने में पूरे मनोयोग से अपनी भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विशिष्ट सहायक डॉ. सूरज सिंह नेगी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) भोमाराम, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत एवं भारत टैक्सी के सिटी हैड (जयपुर) अभिषेक चारण उपस्थित रहे।

CBI का बड़ा खुलासा-होमबॉयर्स फ्रॉड केस में बिल्डर-बैंक नेक्सस बेनकाब, 9वीं चार्जशीट दाखिल

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। सीबीआई ने होमबॉयर्स फ्रॉड से जुड़े एक बड़े मामले में अहम खुलासा करते हुए बिल्डर-बैंक नेक्सस का पर्दाफाश किया है। एजेंसी ने इस मामले में मेसर्स मंजू जे होम्स इंडिया लिमिटेड, उसके निदेशकों और ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (ष्ट्रक्च) ने मेसर्स मंजू जे होम्स इंडिया लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ 9वीं चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां आरोपियों पर वित्तीय संस्थानों और निर्दोष घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक अधिकारियों व अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। आरोप है कि उन्होंने झूठे वादों और भ्रामक जानकारी के जरिए होमबॉयर्स और निवेशकों को गुमराह किया और अवैध तरीकों से आर्थिक लाभ उठाया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ बैंक अधिकारियों ने निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और बिल्डर के अवैध कार्यों में सहयोग किया। इससे न केवल बैंकिंग संस्थानों को नुकसान हुआ, बल्कि घर खरीदने वाले भी ठगे गए। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग जैसे आरोप लगाए हैं। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य मिले हैं, जो फंड डायवर्जन, पद के दुरुपयोग और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की साजिश की पुष्टि करते हैं।

पुलिस मुख्यालय में IAS प्रोबेशनर्स का भ्रमण, DGP राजीव कुमार शर्मा संग विशेष संवाद

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। पुलिस मुख्यालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल ने आधिकारिक भ्रमण किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य सेवा में कदम रख रहे इन युवा अधिकारियों को पुलिसिंग के बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था के व्यावहारिक पहलुओं और पुलिस व प्रशासन के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने की बारीकियों से रूबरू कराना था। इस दौरान महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के साथ प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों का एक विशेष संवाद सत्र आयोजित हुआ, जिसमें डीजीपी श्री शर्मा ने फील्ड में सफल प्रशासनिक नेतृत्व के लिए पुलिस और प्रशासन के बेहतर तालमेल को अपरिहार्य बताया। महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन्स आनंद कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है।

राज्य मे सड़क सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य व स्थिति पर महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल ने व्यावहारिक दिशा-निर्देश साझा किए और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्टेट पुलिस फ्रेमवर्क विषय पर प्रस्तुतीकरण देते हुए राजस्थान पुलिस की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी। राजस्थान में ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट तथा मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जिला स्तर पर नार्को कोऑर्डिनेशन समिति (ह्रष्ह्रक्रष्ठ) की भूमिका और पर महानिरीक्षक पुलिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स श्री विकास कुमार ने प्रकाश डाला।

तकनीकी और समसामयिक चुनौतियों से निपटने के सत्र में उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने प्रोबेशनर्स को साइबर अपराध एवं डिजिटल खतरों% से अवगत कराया।

इस दौरान दल ने 1930 साइबर कंट्रोल रूम का प्रत्यक्ष दौरा कर ठगी के मामलों में की जाने वाली त्वरित तकनीकी कार्रवाई को देखा।

उप महानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स श्वेता धनखड़ ने महिला, बच्चों और कमजोर वर्गों के अधिकारों व सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा संचालित की जा रही विशेष योजनाओं के बारे में अधिकारियों को ब्रीफ किया।

भ्रमण कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों ने जयपुर कमिश्नरेट स्थित अत्याधुनिक अभय कमांड सेंटर% का अवलोकन किया। वहां जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शहर की डिजिटल निगरानी, सीसीटीवी सर्विलांस, ई-चालान और आपातकालीन रेस्पॉन्स सिस्टम की कार्यप्रणाली का सजीव प्रदर्शन कर अधिकारियों को आधुनिक स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल से परिचित कराया।

सहकारिता मंत्री की प्रेरणा से प्रदेश भर में प्रारम्भ हुआ 'परिंडा बांधो अभियान', आगन्तुकों के लिए कार्यालयों में छाया-पानी का भी किया जा रहा बंदोबस्त

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बुधवार को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) परिसर में परिंडा बांधकर विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गए 'परिंडा बांधो अभियान' का शुभारम्भ किया। भीषण गर्मी में बेजुबान पशु-पक्षियों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्री की प्रेरणा से सहकारिता विभाग ने यह अभियान शुरु किया है। अभियान के अंतर्गत विभागीय कार्यालयों, शीर्ष एवं केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंक शाखाओं, केवीएसएस तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के परिसरों, भवनों की छतों, वृक्षों की शाखाओं एवं सुरक्षित छायादार स्थानों पर मिट्टी के परिंडे व जल पात्र लगाए जाएंगे। साथ ही, पक्षियों के लिए चुग्गे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के अंतर्गत सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय एवं नेहरू सहकार भवन में विभागीय व सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ परिंडे बांधे।

शासन सचिव ने कहा कि सहकारिता विभाग अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से इस अभियान को जन-आन्दोलन का स्वरूप देगा। उन्होंने निर्देश दिए कि लगाए गए परिंडों एवं जल पात्रों की प्रतिदिन नियमित सफाई की जाए तथा उनमें स्वच्छ पेयजल भरा जाए। जल को प्रतिदिन बदला जाए ताकि जल दूषित न हो और मच्छरों अथवा जलजनित बीमारियों की आशंका न रहे। साथ ही, चुग्गा पात्रों में भी नियमित रूप से दाना डालने की व्यवस्था की जाए। विभाग ने जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजन से भी इस पुण्य कार्य में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। अभियान के अंतर्गत सहकारी समितियों से जुड़े किसानों, पशुपालकों एवं नागरिकों को अपने घरों, खेतों एवं सार्वजनिक स्थलों पर परिंडे बांधने और जल पात्र रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया एवं जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।

शासन सचिव ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीव-जंतुओं का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। राजस्थान की सांस्कृतिक परम्पराएं भी जीव-दया, करुणा एवं पर्यावरण संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसे में सहकारिता विभाग का यह अभियान केवल मूक पशु-पक्षियों को राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में संवेदनशीलता, करुणा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

आगंतुकों के लिए छाया-पानी की व्यवस्था

शासन सचिव ने विभाग के अधीन संचालित समस्त सहकारी समितियों एवं कार्यालयों को निर्देशित किया है कि कार्यालयों में आने वाले किसानों, उपभोक्ताओं एवं आमजन के लिए स्वच्छ एवं शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय एवं समिति परिसर में छायादार विश्राम स्थल की व्यवस्था करने, बैठने हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गर्मी से राहत के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा एवं स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने में सक्रिय योगदान की अपेक्षा की है।

राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, आमजन को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं-वी श्रीनिवास

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ राज्य है, जिसके माध्यम से पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की नियमित आपूर्ति निरंतर जारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य को आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में कार्यरत तेल एवं गैस कंपनियों को निर्देशित किया कि जिला-वार पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की उपलब्धता एवं वितरण का डेटा प्रतिदिन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उपलब्ध स्टॉक एवं वितरण व्यवस्था की दैनिक समीक्षा की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की अफवाह या कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न न हो सके। मुख्य सचिव ने पेट्रोल एवं डीजल की ड्रमों में बल्क ओपन बिक्री पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से ईंधन की बिक्री एवं संभावित लीकेज को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन अफवाहों पर ध्यान न दे और पैनिक बाइंग ना करें ताकि पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला पर दवाब की स्थिति ना बने।

राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ राज्य है, जिसके माध्यम से पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की नियमित आपूर्ति निरंतर जारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य को आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि विभागीय स्तर से प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री रोकने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है।

बैठक में बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश में ईंधन एवं गैस सप्लाई करने वाली निजी कंपनियों के प्रतिनिधि, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

रक्तरंजित राहों पर शांति का संकल्प

(लेखक- सुनील कुमार महला /)

(21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस विशेष)

किसी कवि ने क्या खूब लिखा है-आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो। हाथ खोल दो वीरों के अब महायुद्ध हो जाने दो। भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए वास्तव में आतंकवाद आज पूरी मानवता के लिए एक नासूर बन चुका है।सच तो यह है कि यह ऐसा दंश है, जिसमें केवल जहर ही जहर भरा है। आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और असमानता जैसी समस्याएँ अपनी जगह हैं, किंतु आतंकवाद इन सबमें सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे मानव सभ्यता, शांति और राष्ट्रीय एकता पर हमला करता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इसका समूल नाश आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।

पाठक जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस (एंटी टेररिज्म डे) मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में उनकी स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुमबुदुर में एक आत्मघाती आतंकी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। वास्तव में,इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और उग्रवाद से दूर रखना तथा समाज में शांति, एकता और सद्भाव का संदेश देना है। सरल शब्दों में कहें तो यह दिवस लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का दिन है।दरअसल, इस दिवस का उद्देश्य केवल आतंकवाद का विरोध करना भर नहीं है, बल्कि समाज में भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना भी है। यह दिन युवाओं को आतंकवाद और कट्टरता के खतरों से अवगत कराता है तथा हिंसा के स्थान पर संवाद, लोकतांत्रिक सोच और मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही आतंकवाद से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और नागरिकों में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता अर्थात जीरो टॉलरेंस की भावना विकसित करने का संदेश भी देता है।इस दिन देशभर के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों द्वारा आतंकवाद विरोधी शपथ ली जाती है। इस प्रतिज्ञा में बिना किसी धर्म या संप्रदाय का नाम लिए मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा देने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने का संकल्प लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों और संस्थानों में वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, सेमिनार, व्याख्यान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में शहीद हुए जवानों और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। राजीव गांधी की हत्या भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित आतंकी घटनाओं में से एक थी। यह हमला श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम यानी एलटीटीई द्वारा किया गया था। एक महिला आत्मघाती हमलावर 'थानु' (धनु) ने फूलों का हार पहनाने के बहाने विस्फोट कर दिया, जिसमें राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए। विशेष सुरक्षा समूह यानी विशेष सुरक्षा समूह(एसपीजी) के नियमों को अत्यंत सख्त बनाया गया तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा दायरे में लाया गया।

यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि एलटीटीई यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका का एक अलगाववादी गुरिल्ला संगठन था, जिसने श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भागों में तमिलों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र तमिल ईलम की मांग को लेकर लगभग तीन दशकों तक सशस्त्र संघर्ष किया। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन द्वारा की गई थी। प्रभाकरन अंत तक इस संगठन का सर्वोच्च और तानाशाही कमांडर बना रहा। एलटीटीई का आत्मघाती दस्ता ब्लैक टाइगर्स कहलाता था, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और अनुशासित आत्मघाती दस्तों में गिना जाता था।दरअसल, श्रीलंका (तत्कालीन सीलोन) को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद वहाँ बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जातीय तनाव बढ़ने लगा। तमिलों का आरोप था कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा और नागरिकता के मामलों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी असंतोष ने धीरे-धीरे उग्रवाद का रूप ले लिया और एलटीटीई जैसे संगठन का जन्म हुआ। शुरुआत में श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचारों के कारण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में, एलटीटीई के प्रति सहानुभूति थी। वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी, लेकिन एलटीटीई ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना से ही संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए। अंततः 21 मई 1991 को एलटीटीई ने आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एलटीटीई को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और उसकी फंडिंग कमजोर पड़ती गई। अंततः वर्ष 2006 से 2009 तक चले चौथे ईलम युद्ध में श्रीलंकाई सेना ने एलटीटीई को पूरी तरह पराजित कर दिया तथा 18 मई 2009 को प्रभाकरन की मृत्यु के साथ ही संगठन का अंत हो गया।

वास्तव में, अपने राजनीतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग ही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अंततः यह उन लोगों को भी नष्ट कर देता है जो इसका समर्थन या अभ्यास करते हैं। आतंकवाद राष्ट्रीय सद्भाव, शांति और सामाजिक एकता को गहरी क्षति पहुँचाता है। सच तो यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म, राष्ट्रीयता या मानवीय उद्देश्य नहीं होता। यह मानवता के विरुद्ध हिंसा और अमानवीयता की पराकाष्ठा है।महात्मा गांधी ने कहा था-मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। गांधीजी ने सदैव अहिंसा, शांति और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कभी भी हिंसा और आतंकवाद को उचित नहीं माना। वास्तव में आतंकवाद स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंसा कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती।

प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हरिओम पंवार की पंक्तियाँ भी इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक प्रतीत होती हैं- बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता।हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। आज आतंकवाद केवल भारत की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की गंभीर समस्या बन चुका है। विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों में आतंकवाद तेजी से फैल रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों, विशेषकर यूनाइटेड नेशंस में बार-बार यह चिंता व्यक्त की है, कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि जिन देशों में आतंकवाद से निपटने की क्षमता का अभाव है, उनकी सहायता की जानी चाहिए। भारत सदैव पंचशील, शांति, संयम और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों में विश्वास करता आया है तथा धर्म, जाति, संस्कृति और आस्था से परे हर प्रकार के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता रहा है। हाल फिलहाल,यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस साल यानी कि वर्ष 2026 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रहार नामक भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति जारी की गई है। इसका उद्देश्य आतंकवाद, कट्टरपंथ, साइबर हमलों, ड्रोन खतरों तथा संगठित आतंकी नेटवर्क से समन्वित तरीके से निपटना है। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नार्वे में 19 मई 2026 मंगलवार को तीसरे भारत-नार्डिक समिट में हिस्सा लिया है, जहां नार्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता जुटे। अच्छी बात यह रही कि इस समिट के दौरान सभी नेताओं ने हर प्रकार के आतंकवाद और कट्टरपंथ की कड़ी निंदा करते हुए सीमापार आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जरूरत बताई है। इतना ही नहीं,इस समिट के दौरान जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले की भी कड़े शब्दों में निन्दा की गई है।

बहरहाल, आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में शांति, सद्भाव, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत किया जाए। आतंकवाद से लड़ना केवल सरकारों या सुरक्षा एजेंसियों का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें मानव जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए हर प्रकार की विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध सजग रहना होगा।

अंत में किसी कवि की इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ बात समाप्त करना उचित होगा-हर घर में दीप जलाना होगा, आतंकवाद के अँधेरे को मिटाना होगा।'अ' से अमरुद, 'च' से चरखा छोड़, 'अ' से अमन, 'च' से चैन पढ़ाना होगा। मेरी धरती, मेरा देश छोड़, हमारी धरती, हमारा देश सिखाना होगा। हर एक देश के नागरिक को अब, देश का पहरेदार बनाना होगा। धरती माँ की छाती से 'आतंकवाद' शब्द को मिटाना होगा। वास्तव में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें यह संदेश देता है कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। शांति, संवाद, शिक्षा और मानवीय मूल्यों के माध्यम से ही आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। यह दिवस प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की एकता, अखंडता और मानवता की रक्षा के लिए सजग रहने की प्रेरणा देता है।

(-सुनील कुमार महला, फीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।)

संपादकीय

कोर्ट की सख्ती के मायने

जन-सुरक्षा व पशु-कल्याण के बीच हो संतुलन

इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय निकायों द्वारा आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में विगत में दिए अपने निर्देशों को नरम न करने का सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, बिगड़ते जन-सुरक्षा संकट में एक आवश्यक हस्तक्षेप है। हाल के वर्षों में, देश भर में स्थानीय प्रशासन व निकाय कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही चिंताजनक वृद्धि को रोकने में विफल ही रहे हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन स्तर पर इस समस्या के निराकरण की कोई सार्थक पहल न होते देख ही, शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, साल 2023 में तीस लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए थे। उसके अगले साल 2024 में रोकथाम के कोई ठोस प्रयास न होने के कारण 37 लाख मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन प्रतिदिन दस हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई राज्यों व शहरों में इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। हाल ही में सामने आए केरल के आंकड़ों के अनुसार, वहां एक साल के भीतर ही 3.6 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ही महीनों में हजारों शिकायतों के बाद हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इन शिकायतों में स्कूलों के पास उनका जमावड़ा होना, चलने में असमर्थ बुजुर्ग नागरिकों का शिकार बनना व आम नागरिकों के आवारा कुत्तों के भय में जीने के मामले उजागर हुए हैं। दरअसल, विगत में भी इस संकट के कारगर समाधान के लिये शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे। स्थानीय नगर निगम व नगर पालिकाओं की जवाबदेही तय की थी कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर उनकी नसबंदी की जाए और टीकाकरण किया जाए। लेकिन इस दिशा में कारगर पहल होती नजर नहीं आई। वहीं तसवीर का दूसरा पहलू है कि यह संकट समाज और संस्थाओं द्वारा जानवरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में परेशान करने वाली विफलता को भी दर्शाता है। पिछले दिनों चंडीगढ़ से एक स्तब्धकारी घटना ने हर किसी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित किया,जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पिल्ले को धधकते तंदूर में फेंककर जिंदा जला दिया। ऐसे शर्मनाक कृत्य उस भयावह क्रूरता को उजागर करते हैं, जो सार्वजनिक चर्चाओं में उजागर नहीं होती। इस घटना ने इन जीवों की दयनीय स्थिति को ही उजागर किया। वहीं भूख से बिलबिलाते कुत्तों द्वारा कथित तौर पर अपने ही बच्चों को खाने के मामले भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है कि जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार का मतलब नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी करना नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही जन सुरक्षा को पशु कल्याण की उपेक्षा का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता है। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जानवरों को स्थानांतरित करने पर दिए गए जोर के साथ अब आश्रय स्थलों, नसबंदी केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और पशु चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश करने की सख्त जरूरत है। निश्चय ही यह चुनौती एक जटिल विषय है। सही मायनों में चुनौती यह भी है कि एक मानवीय, जवाबदेह और प्रभावी आवारा पशु प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो नागरिकों और कुत्तों , दोनों के हितों की रक्षा कर सके। हमेशा से ही कुत्ते की गिनती मनुष्य के वफादार साथी के रूप में की जाती रही है। सदियों से दोनों एक साथ रहे हैं।

क्या है भारत में विद्या व विद्यार्थियों का भविष्य

(लेखिका- निर्मल रानी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा देश से की जा रही मन की बात के 131वें एपिसोड में गत 22 फ़रवरी 2026 को छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की थी। अपने इस संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिये गये उपदेशों में कहा कि अंकों से किसी की योग्यता तय नहीं होती। शिक्षा जीवन को संवारने का एक माध्यम है, जबकि परीक्षा केवल आत्म-मूल्यांकन का ज़रिया है। उन्होंने छात्रों से परीक्षा को किसी बड़े बोझ या हौवे के रूप में देखने के बजाय इसे एक उत्सव की तरह मनाने की अपील की थी । पढ़ाई, आराम, शारीरिक खेलकूद और अपने शौक़ के बीच एक सही संतुलन बनाने को ज़रूरी बताया था। मोदी ने छात्रों को सलाह दी थी कि कुछ छात्र रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ सुबह जल्दी, अपनी इसी मूल शैली पर विश्वास रखें। उन्होंने छात्रों को यह सलाह भी दी कि वे अपने मन की चिंताओं को अपने माता-पिता और परिवार के साथ खुलकर साझा करें, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। अभिभावकों को सलाह देते हुये उन्होंने कहा था कि माता-पिता को बच्चों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध विशिष्ट करियर चुनने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है। इसी तरह उन्होंने शिक्षकों को भी सलाह दी कि उन्हें छात्रों की सीखने की गति को समझना चाहिए और उनके लिए ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जो पहुंच में हों लेकिन जिन्हें प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े।

प्रधानमंत्री के उपरोक्त कथन में यह बात पूरी तरह विरोधाभासी है कि अंकों से किसी की योग्यता तय नहीं होती। क्योंकि आज के दौर में एडमिशन,वरीयता सूची,श्रेणी निर्धारण,चयन आदि हर जगह अंक प्रतिशत की ही होड़ लगी हुई है। परन्तु प्रधानमंत्री ने इन्हीं छात्रों को कभी यह नहीं बताया कि यदि आपकी जी तोड़ मेहनतों के बाद परीक्षा के पर्चे लीक हो जायें व परीक्षा ही स्थगित कर दी जाये तो आख़िर छात्रों को ऐसे सदमे से कैसे उबरना चाहिये। और जो छात्र इस कुप्रबंधन का शिकार होकर किसी कारणवश पुनः परीक्षा में बैठने योग्य न रह सके और इसी कारण उसका जीवन व भविष्य चौपट हो जाये उस छात्र को उसके अभिभावकों को या फिर सरकार अथवा इस दुर्व्यवस्था के ज़िम्मेदारों को क्या करना चाहिये ? हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर जुलाई 2024 में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपना आधिकारिक बयान दे चुके है। उन्होंने संसद में देश के हर छात्र और नौजवान को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों और पेपर लीक को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी या माफ़िया को क़तई बख़्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रणाली और पूरे सिस्टम को पुख़्ता व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर क़दम उठाने की बात कही थी।

परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भी पेपर लीक की घटना समाप्त नहीं हुई है। अभी इसी मई 2026 में आयोजित हुई नीट परीक्षा को पेपर लीक विवादों और धांधली की शिकायतों के बाद सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है और अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस परीक्षा में 22,05,035 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। आज इन 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। पेपर लीक और उसे रद्द किए जाने से उपजे मानसिक तनाव के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों से कम से कम 4 छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की दुखद ख़बरें सामने आई हैं। इनमें एक छात्र प्रदीप मेघवाल (उम्र 22 वर्ष) राजस्थान के झुंझुनूं ज़िले का था जबकि ऋतिक मिश्रा (उम्र 21 वर्ष) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का निवासी था। यह ऋतिक का नीट परीक्षा का तीसरा प्रयास था और वे इस बार चयन को लेकर बेहद आश्वस्त था। परीक्षा रद्द होने की ख़बर से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया था। इसी तरह 20 वर्षीया अंशिका दिल्ली के आज़ादपुर (आदर्श नगर) इलाक़े की रहने वाली थी। जबकि 17 वर्षीय सिद्धांत हेगड़े दक्षिण गोवा के कर्टोरिम का रहने वाला था। हेगड़े पेपर लीक की घटना से इतना आहत था कि उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह अब और प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं देना चाहता।

एक तरफ़ तो नीट पेपर लीक के चलते 22 लाख से अधिक मेधावी छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है साथ ही देश में गत 10 वर्षों के दौरान भारत में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ़ लाखों रूपये ख़र्च कर अयोग्य व निठल्ले लोग डॉक्टर्स की फ़र्ज़ी डिग्री लेकर मरीज़ों की जान से खिलवाड़ करते फिर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले से पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे सरकारी संजीवनी क्लीनिकों में MBBS की फ़र्ज़ी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे 3 नक़ली डॉक्टरों को गिरफ़्तार किया। ग्वालियर निवासी कुमार सानू शाक्य, देवेंद्र चौधरी और जबलपुर के पल्लव जैन ने गिरफ़्तारी के बाद पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी MBBS की डिग्रियां और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट 8,00,000 से 10,00,000 तक में ख़रीदे थे। दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जब दस्तावेज़ों का वेरिफ़िकेशन कराया गया, तो डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी तरह फ़र्ज़ी पाए गए। सवाल यह है कि जब नीट जैसी अति महत्वपूर्ण परीक्षा के इतिहास में अब तक 5 बार बड़े स्तर पर पेपर लीक और धांधली के गंभीर मामले सामने आ चुके हों जिनकी आधिकारिक जांच या अदालती कार्यवाही भी हुई हो। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हों जिससे करोड़ों मेधावी छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है उधर 8 -10 लाख रुपये में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की जा रही हो ऐसे में भारत में विद्या व विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में आसानी से सोचा जा सकता है।

गतिशील रहें

एक यात्री जा रहा था। अंधेरी रात थी। उसे लम्बा रास्ता तय करना था। एक व्यक्ति ने उसे लालटेन देते हुए कहा, इसके प्रकाश में तुम अपना रास्ता देख पाओगे। मार्ग सुख से कटेगा। इसे ले जाओ। उस यात्री ने देखा कि लालटेन का प्रकाश तीन-चार फीट तक फैल रहा है। उसके मन में संदेह हुआ कि रास्ता बहुत लंबा है। प्रकाश केवल तीन-चार फीट तक ही पड़ता है। रास्ता पार कैसे कर पाऊंगा? वह उलझ गया और उलझता ही गया। वह बोला, तीन-चार फीट का प्रकाश मुझे दस मील की यात्रा कैसे करा पाएगा?

यह विधि को न समझने के कारण है। विधि को समझे बिना साधक उलझ जाते हैं। विधि को ठीक समझ लेते हैं तो तीन-चार फीट का प्रकाश दस मील की यात्रा करा सकता है। यह प्रकाश दस मील के पूरे पथ को प्रकाशित कर सकता है। आप चलते चलें, दस मील का रास्ता प्रकाशित हो जाएगा और यदि उसी बिन्दु पर खड़े रह गए तो दो फीट का रास्ता ही प्रकाशित होगा, शेष अंधकार ही अंधकार रहेगा। आवश्यकता है चलने की, सतत गतिशील रहने की।

विधि को समझें और चलें। विधि को समझना ही पर्याप्त नहीं है, चलना भी पड़ेगा। आगे से आगे बढ़ना होगा। यदि नहीं चले, रूके रह गए तो प्रकाश जहां पड़ता है वहीं पड़ेगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा। वह तभी बढ़ेगा, जब हम बढ़ेंगे।

वह हमारे रूकने के साथ रूकेगा और बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अभ्यास करते जाएं। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मंजिल स्वत- मिल जाएगी।

विचार मंथन

पश्चिम बंगाल में काली के पुजारियों का भत्ता बंद

(लेखक- सनत जैन)

- सनातनी अब मांसाहारी और शाकाहारी में बंटे

पश्चिम बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम बंगाल के इमाम और पुजारियों को जो भत्ता ममता सरकार द्वारा दिया जा रहा था, 1 जून 2026 से दोनों के भत्ते बंद करने का निर्णय किया है। इस निर्णय की पश्चिम बंगाल में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। टीएमसी के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी साल मार्च माह से धार्मिक नेताओं के भत्ते में 500 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि की थी। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों के इमाम को हर महीने 3000 रूपये तथा पुजारियों को 2000 रूपये की मदद दी जा रही थी। भाजपा की सरकार ने अब यह मानदेय बंद करने का निर्णय लिया है। इसका असर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में हिन्दू-मुस्लिम के बीच होना तय है। पश्चिम बंगाल में काली की पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में पूजा में बली और खाने-पीने में मांसाहार का बड़ा उपयोग होता है। बंगाल में हजारों की संख्या में पुजारियों को यह मानदेय मिल रहा था। पुजारियों को आशा थी, नई सरकार इमाम और मुअज्जीन का भत्ता बंद करेगी। हिंदू पुजारियों को 3000 रूपये महीने का मानदेय देने का निर्णय करेगी। सरकार ने दोनों समुदाओं के धार्मिक गुरुओं का भत्ता बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दो अलग-अलग भागों में बांटा जा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व हिंदुओं में वैष्णव और शेव शाक्त के बीच में विवाद होते रहे हैं। हिन्दू समुदाय तीन भागों में बटे हुए थे। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में इसी विवाद को फिर से खड़ा कर दिया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदुओं के नाम पर लड़ा है। हिंदू पुजारियों को आशा थी, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकार ने बढ़ाने के स्थान पर बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के उद्घोष के साथ वहां पहुंची है। बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से बंगाली पुजारियों में जबरदस्त नाराजी देखने को मिल रही है। उनका मानना है वह शाक्त भक्त हैं, मां काली की पूजा करते हैं। काली की तांत्रिक पूजा अलग तरह की होती है, जिसे वैष्णव और शैव स्वीकार नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सरकार बनने के बाद सरकार, पश्चिम बंगाल के पुजारियों के साथ हिन्दुओं में जो भेदभाव कर रही है। उससे यह धारणा बन रही है, पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की सरकार हिंदुओं को हिंदुओं के बीच में बांटने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रारंभ में ही यदि इस तरह के भेदभाव की भावना हिंदुओं के बीच में जागृत होती है, तो यह हिंदू एकता को लेकर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान यह मामला कहीं ना कहीं सामने आया था। उत्तर भारत के जो नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में गए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांस और मछली खाकर यह विश्वास दिलाया था, वह बंगाल की संस्कृति और बंगाल की धार्मिक परंपरा के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। सरकार बनने के बाद जिस तरह से कालीभक्त पुजारियों के मानदेय को सरकार ने बंद किया है। उसके बाद वहां पर कहा जा रहा है, वर्तमान सरकार काली भक्तों को पसंद नहीं करती है। पश्चिम बंगाल की धार्मिक संस्कृति में भगवान राम और अन्य हिंदू देवी देवता जो शैव और वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में साक्त भक्तों में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुए हैं। लाखों की संख्या में अर्ध सैनिक बल तैनात किया गया। लगभग एक करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए। पश्चिम बंगाल के बाहर से अधिकारियों को लाकर चुनाव कार्य में लगाया गया। दो तिहाई बहुमत से जीतने के बाद भी भाजपा को वह जन समर्थन बंगाल में अभी नहीं मिल रहा है, जो इतनी बड़ी जीत के बाद भाजपा को मिलना चाहिए था। जिस तरह का निर्णय सुवेंदु अधिकारी ने लिया है, उसमें हिंदुओं के मन में यदि यह बात आ गई, तो भाजपा को राजनीतिक तौर पर इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों से अपनी दूरियां जग जाहिर हैं। यदि वह इमाम और मुअज्जिन के भत्ते को बंद कर देती, तो इसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं के बीच बेहतर होती। सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के बीच विभाजन की बात अब खुले आम होने लगी है। जो पश्चिम बंगाल की सरकार और भाजपा के लिए आने वाले समय पर नुकसानदेह साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जो जीत हुई है उससे लगता है, भाजपा के नेता सत्ता के नशे में मदहोश हो चुके हैं। निर्णय लेते वक्त वह सोच समझकर निर्णय नहीं ले रहे हैं। जोश में होश खोने के स्थान पर पश्चिम बंगाल सरकार को ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा, यही कहा जा सकता है।

शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद

सेंसेक्स 117, निफ्टी 41 अंक उछला

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। आज एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ ही दुनिया भर के बाजारों से मिलेजुले संकेतों से बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो के तेजी से भी बाजार को बल मिला। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 117.54 अंक बढ़कर 75,318.39 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 41 अंक उछलकर 23,659 अंक पर बंद हुआ।

आज रिलायंस के अलावा बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, इंडिगो, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी तेजी रही। वहीं दूसरी ओर बीईएल, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, भारती एयरटेल और इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट आई। निफ्टी के शेयरों में हिंडाल्को में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं ब्रॉडर बाजार में निफ्ट मिडकैप में 0.49 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.04 फीसदी तेजी आई। निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी ऑटो में तेजी रही जबकि निफ्टी मीडिया और निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट आई। वहीं इससे पहले आज सुबह शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत रही। सुबह सेंसेक्स 500 के करीब टूटकर 74,681 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी भी 150 अंकों से ज्यादा गिरकर 23,464 के स्तर पर पहुंच गया। आज दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल से एशियाई बाजारों पर दबाव पड़ा। अमेरिकी और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण भी अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी रही। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निकेई 225 करीब 1.29 फीसदी और दक्षिण कोरिया

का कोस्पी करीब 0.93 फीसदी नीचे आया। डाओ जोंस करीब करीब 0.65 फीसदी गिरा। वहीं एसएंडपी 500 भी 0.67 फीसदी नीचे आया। नेसडेक कंपोजिट भी 0.84 फीसदी टूटा।

रुपया गिरावट पर बंद

मुम्बई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ ही 96.85 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये पहली बार 96 के स्तर से आगे निकल गया। ये शुरुआती कारोबार में 96.89 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा। वहीं गत दिवस रुपया 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। बुधवार को इसकी शुरुआत 96.86 के स्तर पर हुई। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में रुपया करीब 1 रुपये तक कमजोर हो चुका है। रुपये पर सबसे अधिक दबाव कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गयी हैं। आज ब्रेंट क्रूड करीब 111 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण भी कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है। इससे भारत पर भी दबाव आया है। भारत को काफी तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में कच्चा तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव बढ़ जाता है। रुपये की कमजोरी की दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता है। निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जा रहे हैं, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत होने से भी भारतीय रुपये पर दबाव आया है।

भारत के अरबपतियों की संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर हुई, 26 नए अरबपति बने

मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे अमीर तो अडाणी दूसरे नबंर पर

मुंबई।

भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। हाल ही में 26 नए अरबपतियों के जुड़ने के बाद भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला तीसरा देश बन गया है। देश में अरबपतियों की कुल संख्या बढ़कर 229 हो गई है।

फोर्ब्स की ताजा सूची के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी करीब 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं, जबकि उद्योगपति परिवार की प्रमुख सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला के रूप में तीसरे नंबर पर हैं। इस सूची में स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल चौथे और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर पांचवें नंबर पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे वे साल के सबसे बड़े गेनर बनकर उभरे हैं। वहीं, भारतीय उद्योग जगत में पारंपरिक कारोबारियों के साथ नए दौर के टेक उद्यमियों की मौजूदगी भी तेजी से बढ़ रही है। मुंबई अब भी भारतीय अरबपतियों का सबसे बड़ा केंद्र है। वित्त, उद्योग, शेयर बाजार और स्टार्टअप निवेश का प्रमुख केंद्र होने के कारण मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि, डिजिटल कारोबार का विस्तार और स्टार्टअप संस्कृति ने संपत्ति निर्माण की रफ्तार को नई ऊंचाई दी है।

इस बार की सूची में कई युवा और नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। खासतौर पर एआई, फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। इनमें 31 साल के अरविंद श्रीनिवास जैसे युवा फाउंडर्स का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बढ़ती उद्यमिता, निवेशकों का विश्वास और तकनीक आधारित कारोबार आने वाले सालों में अरबपतियों की संख्या और संपत्ति दोनों को और बढ़ा सकते हैं। इससे भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है।

मेटा ने किया हजारों कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान, एआई का असर

कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से छंटनी की सूचनाएं भेजना किया शुरू

नई दिल्ली।

मेटा प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को करीब 8,000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया। इसकी वजह एआई के कारण संगठन का पुनर्गठन है। इसकी जानकारी कई रिपोर्ट्स में दी गई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से छंटनी की सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसके करीब 10 फीसदी कर्मचारियों के प्रभावित होने और भूमिकाओं में बदलाव होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक इंटरनल मेमो में मेटा की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत करीब 7,000 कर्मचारियों को एआई-केंद्रित नई भूमिकाओं में स्थानांतरित करने की योजना का जिक्र किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में मेटा की एचआर चीफ जेनेल गेल ने कहा कि कई टीमों को एआई-आधारित सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि सरल संरचनाएं और छोटे समूह बनाए जा सकें जो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ तेजी से काम किया जा सके। गेल ने कहा कि बदलावों पर काम करते हुए कई टीमों ने एआई-आधारित डिजाइन सिद्धांतों को अपनी नई संगठनात्मक संरचनाओं में शामिल किया।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अमेरिकी कर्मचारियों को भी छंटनी के प्रभावी होने वाले दिन घर से काम करने के लिए कहा गया था, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन मेटा ने पिछली छंटनी घोषणाओं के दौरान भी किया था।

Meta AI

यह पुनर्गठन ऐसे समय में हो रहा है जब मेटा एआई बुनियादी ढांचे पर खर्च में काफी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 2026 के लिए 125 अरब डॉलर से 145 अरब डॉलर के बीच पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है, जो मुख्य रूप से एआई डेटा केंद्रों, कस्टम चिप्स और मॉडल प्रशिक्षण पर केंद्रित है। सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कर्मचारियों को बताया कि एकत्रित डेटा का उद्देश्य केवल एआई प्रणालियों को बेहतर बनाना है, न कि निगरानी करना।

मारुति सुजुकी ने लखनऊ में खोली स्मार्ट फैक्ट्री लैब

युवाओं को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण

लखनऊ।

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुजुकी कंपनी ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक अत्याधुनिक स्मार्ट फैक्ट्री लैब की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य डिप्लोमा छात्रों को आधुनिक विनिर्माण तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। यह लैब अपने पहले वर्ष में करीब 400 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। यहां छात्रों को स्वचालन, उद्योग 4.0, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी), न्यूमेटिक्स, ऊर्जा मापन और गति नियंत्रण प्रणालियों सहित उन्नत औद्योगिक तकनीकों का सीधा अनुभव मिलेगा। यह पहल अकादमिक शिक्षा और उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने में सहायक होगी। कंपनी का मानना है कि इस अत्याधुनिक लैब के माध्यम से छात्रों में उद्योग के लिए आवश्यक सही मानसिकता विकसित होगी, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और तकनीकी दक्षता मजबूत होगी। इसका अंतिम लक्ष्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार पेशेवर बनाना है, जो देश के कार्यबल में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट मामलों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी ने कहा, स्मार्ट फैक्ट्री लैब के उन्नयन के साथ, हम सरकार के स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार पेशेवर तैयार कर रहे हैं। ये लैब विनिर्माण क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने, कौशल अंतर को कम करने और छात्रों में उद्योग-विशिष्ट उपकरणों के उपयोग में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण के अवसर प्रदान करेंगी। कंपनी ने भारत और जापान सरकार के सहयोग से चार जापान-भारत विनिर्माण संस्थान (जेआईएम) भी स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, ऑटोमोटिव विनिर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्योग-विशिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 18 आईटीआई में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब (एएमएल) भी स्थापित की गई हैं।

यह कदम युवाओं को उद्योग की मांगों के अनुरूप तैयार करने की मारुति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सेंसेक्स 118 अंक चढ़कर 75,318 पर बंद

निफ्टी में भी 41अंक की तेजी रही; रुपए 96.89 के रिकॉर्ड लो पर

मुंबई। सेंसेक्स बुधवार को 118 अंक चढ़कर 75,318 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 41 अंकों की तेजी रही, ये 23,659 पर पहुंच गया। बुधवार के कारोबार में ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 33 पैसे टूटकर 96.89 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले कई सत्रों से रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 19 मई को सेंसेक्स 114 अंक की गिरावट के साथ 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 32 अंक की गिरावट रही, ये 23,618 पर बुद हुआ। आज के बैंकिंग, एफएमसीजी और मेटल शेयर्स में बिकवाली रही। वहीं आईटी, रियल्टी और मीडिया शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही।

सरकार ऊर्जा संकट के बीच अब इलेक्ट्रिक बस-ट्रकों को बढ़ावा देने की तैयारी में

1 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रहा केंद्र

नई दिल्ली।

भारत सरकार ऊर्जा संकट के बीच प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब डॉलर यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है। इस योजना का मकसद कॉमर्शियल परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम न छापने की शर्त पर मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि यह प्रोग्राम 10 सालों तक चलेगा और मुख्य रूप से भारत के प्राइवेट ओन्ड कॉमर्शियल फ्लीट को टारगेट करेगा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंटर-सिटी बस ऑपरेटरों के लिए रखा जा सकता है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए इस महीने प्रधानमंत्री कार्यालय और इंडस्ट्री से जुड़े पक्षों के साथ बैठकें हो सकती हैं। अंतिम बजट आवंटन, प्रोत्साहन पाने वाले वाहनों की श्रेणी और सब्सिडी ढांचे पर अभी काम चल रहा है और इसमें बदलाव संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के बाद भारत सरकार पेट्रोल, डीजल आदि पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रही है।

इससे ऊर्जा सुरक्षा और आयातित महंगाई को लेकर चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। भारत अपनी करीब 90 फीसदी कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिससे वह वैश्विक भू-राजनीतिक संकट और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना रहता है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक नई दिल्ली जैसे शहरों में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन सालाना सूक्ष्म कण प्रदूषण का लगभग 40 फीसदी तक योगदान देता है। पिछले पांच सालों में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, जिसमें सरकारी परिवहन कंपनियों की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि भारत में अभी भी ज्यादातर नई बसें डीजल से चलती हैं। हालांकि डीजल पर निर्भरता केवल भारत की समस्या नहीं है, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्र कमर्शियल वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन में पहले से ही लाखों इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें चल रही हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप शहरी लॉजिस्टिक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट को तेजी से इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। अनुमानों के मुताबिक भारत में 20 लाख से ज्यादा बसें हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 फीसदी बसों पर सरकार का नियंत्रण है। वहीं देश में करीब सभी ट्रक निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं और यही डीजल की सबसे बड़ी खपत करते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी छोटे कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। ये ऑपरेटर ऊंची शुरुआती लागत और सीमित वित्तपोषण के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। विचाराधीन प्रोत्साहनों में वाहन की पूरी अवधि में प्रति वाहन 15 लाख रुपए तक का ब्याज सब्सिडी लाभ शामिल हो सकता है, जिसे समय के साथ धीरे-धीरे कम किया जाएगा। सरकार प्राइवेट कंपनियों को इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी व्यवस्था पर भी विचार कर रही है।

कर्मचारियों पर कम खर्च और ब्याज में आई कमी का कंपनियों को मिला फायदा

नई दिल्ली।

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनियों का मुनाफा मार्जिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कर्मचारियों पर कम खर्च और ब्याज के बोझ में आई कमी का कंपनियों को फायदा मिला। कम वेतन और पारिश्रमिक के साथ-साथ ब्याज लागत में हुई बचत ने कच्चे माल की बढ़ी लागत को काफी हद तक पाट दिया है। इससे वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनियों का कर बाद मुनाफा मार्जिन 11.3 फीसदी रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 60 आधार अंक ज्यादा है और कम से कम पिछली 21 तिमाहियों में सबसे ज्यादा मुनाफा मार्जिन है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के 10.6 फीसदी मुनाफा मार्जिन से चौथी तिमाही में 70 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनियों का मुनाफा मार्जिन पिछले पांच सालों में करीब एक तिहाई बढ़ा है। मार्च 2021 तिमाही में यह 8.6 फीसदी था। 837 कंपनियों का वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कुल शुद्ध लाभ 15.5 फीसदी बढ़ा है जबकि इस दौरान उनकी आय में 9.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन कंपनियों का कुल समायोजित शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में करीब 3.24 लाख करोड़ रहा जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 2.81 लाख करोड़ रुपए था। दूसरी ओर इन कंपनियों की कुल आय वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में बढ़कर लगभग 28.65 लाख करोड़ रुपए रही जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 26.16 लाख करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 27.71 लाख करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में वेतन और पारिश्रमिक और ब्याज व्यय जैसे प्रमुख खर्च में वृद्धि धीमी रही जिससे कंपनियों को मुनाफा मार्जिन बढ़ाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में नमूने में शामिल कंपनियों की कुल वेतन वृद्धि 6.4 फीसदी रही जबकि बिक्री एवं मार्केटिंग खर्च में 3.6 फीसदी का इजाफा हुआ। हालांकि कंपनियों की लाभप्रदता को सबसे बड़ा फायदा कम ब्याज लागत का मिला। इस लाभ में बैंकों और गैर-बैंक ऋणदाताओं का दबदबा रहा और इनकी हिस्सेदारी नमूने में शामिल कंपनियों के कुल शुद्ध लाभ की करीब 43 फीसदी रही। बैंक, वित्त और बीमा कंपनियों को कम ब्याज दरों से सबसे ज्यादा लाभ हुआ और वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उनके कुल ब्याज खर्च में केवल 2.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

वायु सुरक्षा अधिकारी 'फ्यूल-कंट्रोल स्विच पैनल' के परीक्षण की करेंगे निगरानी

लंदन-बेंगलूरु उड़ान के पायलटों ने इसमें खराबी की बात कही थी

नई दिल्ली।

भारतीय वायु सुरक्षा अधिकारी सिएटल जाने की योजना बना रहे हैं। वहां वे बोइंग द्वारा किए जा रहे एक 'फ्यूल-कंट्रोल स्विच पैनल' के परीक्षण की निगरानी करेंगे। इस पैनल को फरवरी में एयर इंडिया के एक 787 विमान से हटा दिया गया था, जब लंदन-बेंगलूरु उड़ान के पायलटों ने इसमें खराबी की बात कही थी। यह जानकारी दस्तावेज से पता चली है। भारतीय अधिकारियों ने इस परीक्षण को 'संवेदनशील' बताया है। इस परीक्षण ने बोइंग ड्रीमलाइनर में लगे उन स्विचों पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है, जो विमान के इंजनों में जेट ईंधन का प्रवाह नियंत्रित करते हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब जांचकर्ता पिछले जून में गुजरात में हुए एयर इंडिया 787 विमान हादसे की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्विच इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर पायलट कोई विशेष एक्शन नहीं लेते हैं तो इन्हें हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन इस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में यह सामने आने के बाद कि ये स्विच करीब एक ही समय पर बंद हो गए थे और जिससे इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया था, ये स्विच अब जांच के दायरे में आ गए हैं। डीजीसीए ने पहले बताया था कि लंदन में फरवरी में हुई घटना के दौरान पायलटों ने इंजन चालू करते समय देखा कि पहले दो प्रयासों में जब हल्का दबाव डाला गया, तो फ्यूल स्विच 'रन' स्थिति में स्थिर नहीं रहे, लेकिन उड़ान भरने से पहले तीसरे प्रयास में वे स्थिर हो गए। एयर इंडिया ने कहा कि अतिरिक्त परीक्षण में एक नियंत्रित प्रयोगशाला परिवेश में जांच शामिल है, ताकि इसके प्रदर्शन की निश्चित रूप से पुष्टि हो सके।

निवेश के लिए खरीदा फिजिकल गोल्ड सबसे महंगा और घाटे वाला विकल्प

आज भी भारत के घरों में करीब पच्चीस हजार टन सोना पड़ा है

नई दिल्ली।

भारतीय समाज और सोने का रिश्ता सदियों पुराना है। त्योहारों की रौनक हो या शादियों का उल्लास, सोना हर मोड़ पर भारतीय परिवारों के सुख-दुख का साथी रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आज भी भारत के घरों में करीब पच्चीस हजार टन सोना पड़ा है, जो काफी हद तक निष्क्रिय है, अलमारियों में बंद है और जिसकी देश भर में कोई एक तय कीमत भी नहीं है, लेकिन बदलते समय के साथ सोने के बाजार की यह पूरी तस्वीर अब बदल रही है। साल 2024 से सरकार ने नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) को जारी करना पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसके बाद बजट 2026 के नए नियमों ने इसके टैक्स फायदों को भी सीमित कर दिया। दूसरी तरफ नवंबर 2025 में सेबी ने मोबाइल ऐप्स पर मिलने वाले अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलते सिस्टम के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स' (ईजीआर) ने निवेश की दुनिया में कदम रखा। अब देश के आम निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोने में निवेश का सबसे व्यावहारिक, सुरक्षित और किफायती रास्ता कौन सा है। क्या हमें सुनार की दुकान से पारंपरिक सोना खरीदना चाहिए, सालों से चल रहे गोल्ड ईटीएफ में बने रहना चाहिए या फिर नए ईजीआर को अपनाना चाहिए। पारंपरिक रूप से भारत में सोने की खरीद हमेशा से आभूषणों या सिक्कों के रूप में की जाती रही है, जिसे हम फिजिकल गोल्ड कहते हैं। सुनार की दुकान पर जाकर अपनी आंखों के सामने सोने को देखना और उसे छूकर महसूस करना हमेशा से भारतीयों की पसंद रही है। हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इस उपभोक्ता व्यवहार की गहराई को समझाते हुए कहती हैं कि भारत में गहनों और सोने का अपना एक सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है, क्योंकि यह लोगों को 'टैन्जिबल ओनरशिप' यानी संपत्ति को छूकर महसूस करने और खुद के पास सुरक्षित रखने की वास्तविक खुशी देता है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि अगर आप इसे सिर्फ निवेश के नजरिए से देखें, तो फिजिकल गोल्ड सबसे महंगा और घाटे वाला विकल्प साबित होता है। सोना खरीदते ही सबसे पहले आपको 3फीसदी जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा ज्वेलर्स 5फीसदी से लेकर 20फीसदी या उससे भी ज्यादा तक मेकिंग चार्ज वसूल लेते हैं, जिसका निवेश से कोई फायदा नहीं होता। फिर इसकी सुरक्षा की चिंता अलग रहती है। या तो घर में चोरी का डर बना रहता है, या बैंक लॉकर के लिए हर साल मोटा किराया देना पड़ता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप सोना बेचने जाते हैं। उस समय ज्वेलर्स पुराने मेकिंग चार्ज का पैसा तो वापस नहीं देते, ऊपर से शुद्धता जांचने के नाम पर सोने के वजन या कीमत में भी कटौती कर लेते हैं।

तमिलनाडु की सत्ता में 59 साल के बाद वापसी करेगी कांग्रेस, सीएम विजय की कैबिनेट में कल होगी शामिल

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की राजनीति में करीब छह दशक बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं और इस विस्तार में कांग्रेस की सरकार में औपचारिक एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस तरह करीब 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु की सत्ता में सीधे भागीदारी करती नजर आएगी। सूत्रों के मुताबिक, टीवीके और कांग्रेस के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी संकेत दिए हैं कि पार्टी सरकार में शामिल होने जा रही है। लंबे समय तक द्रविड़ राजनीति के प्रभाव वाले तमिलनाडु में कांग्रेस ज्यादातर समय डीएमके या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में रही, लेकिन उसे कभी सरकार में जगह नहीं मिली। अब विजय सरकार में कांग्रेस की एंट्री को दक्षिण भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह कदम 2026 के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ विजय अपनी सरकार को और मजबूत करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच टीवीके ने अपने अन्य सहयोगी दलों को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। मंत्री आधव अर्जुना ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ भी बातचीत जारी है।

अस्पताल के बाहर सलमान का पैपराजी पर फूटा गुस्सा... क्या तुम लोग पागल हो गए हो

मुंबई (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर पैपराजी पर भड़क गए। किसी करीबी से मिलने पहुंचे सलमान की नाराजगी तब सामने आई जब कुछ फोटोग्राफर्स ने अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर हंगामा शुरू किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, सलमान के बाहर आते ही कुछ पैपराजी ने उनकी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' का नाम जोर-जोर से पुकारना शुरू किया। इस पर गुस्साए सलमान ने पूछा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? उन्होंने पैपराजी से सवाल किया कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो, तब क्या उन्हें भी इस तरह कैमरों और शोर-शराबे का सामना अच्छा लगेगा। अभिनेता के गुस्से को देखकर मौके पर मौजूद पैपराजी ने तुरंत माफी मांगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मीडिया ने हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन अस्पताल जैसी जगह पर किसी के निजी पलों को सनसनी बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने संवेदनशीलता की कमी पर जोर देकर कहा, 'मैं 60 साल का हूं, लेकिन लड़ना नहीं भूला।'

आईआरसीटीसी लाया गर्मियों में चारधाम यात्रा का खास मौका

नई दिल्ली (एजेंसी)। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और इस दौरान पहाड़ों की ओर रुख करने वाले परिवारों के लिए आईआरसीटीसी बेहतरीन मौका लेकर आया है। रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने 2026 के लिए अपने विशेष चारधाम यात्रा पैकेज की घोषणा की है, जिसमें यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पैकेज के तहत उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। यह 11 रात और 12 दिन का पैकेज दिल्ली से शुरू होगा और श्रद्धालुओं को आरामदायक एसी टेंपो ट्रैवलर से यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों के लिए ठहरने हेतु अच्छे होटलों की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की सुविधा और प्रतिदिन 1 लीटर पानी की बोतल भी प्रदान की जाएगी। 2026 में यात्रा की तारीखें जून (1, 12, 24), सितंबर (1, 12, 24) और अक्टूबर (1, 15) हैं। प्रति व्यक्ति खर्च इस प्रकार निर्धारित किया गया है। अकेले रुकने पर 75,000, दो लोगों के साथ 62,000 और तीन लोगों के साथ 57,000। वहीं, 5 से 11 साल के बच्चे के लिए (एक्स्ट्रा बेड सहित) 30,000 और बिना एक्स्ट्रा बेड के 20,000 का खर्च आएगा। यह पैकेज परिवार के साथ देवभूमि का आध्यात्मिक अनुभव लेने का एक शानदार अवसर है।

देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में भीषण आग, महिला मरीज की मौत; कई अन्य झुलसे

देहरादून (एजेंसी)। देहरादून के पैनेसिया हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में आईसीयू में भर्ती एक 55 वर्षीय महिला मरीज की मौत हुई, जबकि छह अन्य मरीज और बचाव कार्य में जुटे तीन पुलिसकर्मी भी झुलस गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग एसी में ब्लास्ट होने के कारण लगी, जिसने अस्पताल परिसर में धुएं और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ। हादसे के बाद अस्पताल को आनन-फानन में खाली कराया गया और कई मरीजों को एंबुलेंस के जरिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। कैलाश अस्पताल में भर्ती कराए गए छह झुलसे मरीजों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर विभाग ने आग लगने के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। यह घटना फिर देहरादून के निजी अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कमजोर व्यवस्थाओं को उजागर करती है। राजधानी के अधिकांश अस्पताल सीमित जगह, संकरे रास्तों और अपर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट के साथ संचालित हो रहे हैं, जिससे ऐसी आपात स्थितियों में बचाव कार्य बाधित होता है और मरीजों की जान खतरे में पड़ती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद पूरे परिसर में धुआं भर गया था, जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फायर ऑडिट और मॉक ड्रिल जैसे महत्वपूर्ण इंतजाम अक्सर केवल कागजों तक ही सीमित रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं। प्रशासन आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद ही सक्रिय होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही लापरवाही दोहराई जाती है, जो गंभीर मरीजों की जिंदगी को खतरे में डालती है।

आरएसएस और प्रधानमंत्री संविधान को फाड़ने की कोशिश कर रहे-राहुल गांधी

रायबरेली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर कहा कि भाजपा, प्रधानमंत्री और आरएसएस इसे फाड़ने और फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने तो इसे पहले ही फाड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान की किताब सिर्फ कागज का पन्ना नहीं है, बल्कि इसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और वीरा पासी जैसे अनगिनत लोगों का खून और पसीना मिला हुआ है, जिन्होंने इसे बनाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

बुधवार को रायबरेली के लोधवारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीरा पासी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने एक बार फिर देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर देश के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।

वहीं, गौरीगंज क्षेत्र के तेजी का पुरवा स्थित कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की रक्षा संविधान करता है और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार संविधान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करना है, लेकिन पिछले 12 साल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बनाया जा रहा है और देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी इस देश को नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि टॉफी बांटना बंद करो और किसानों को खाद उपलब्ध कराओ। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी आज भी करोड़ों रुपये का तेल विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है और अडानी-अंबानी को देश का धन देना भी संविधान पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि संविधान हिंदुस्तान की आवाज है।

डीपफेक और एआई कंटेंट के खिलाफ अदालत पहुंचे राघव चड्ढा, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स और निजता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। राघव चड्ढा ने अदालत में याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे डीपफेक वीडियो, छेड़छाड़ किए गए विजुअल, कृत्रिम आवाज क्लोनिंग और भ्रामक डिजिटल सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की अदालत में 21 मई को होने वाली है।

याचिका में कहा गया है कि एआई तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच कई बार सार्वजनिक हस्तियों की आवाज, चेहरा और बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। इससे न केवल उनकी छवि प्रभावित होती है, बल्कि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। राघव चड्ढा ने अदालत से मांग की है कि बिना अनुमति उनके नाम, आवाज, तस्वीर और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर तैयार किए गए किसी भी फर्जी कंटेंट पर तत्काल रोक लगाई जाए। हाल के वर्षों में डीपफेक तकनीक को लेकर देशभर में चिंता लगातार बढ़ी है। राजनीतिक नेताओं, फिल्म कलाकारों और खिलाड़ियों से जुड़े कई फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इससे पहले अभिनेता अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उन्हें राहत भी मिली थी। अब राघव चड्ढा की याचिका को डिजिटल निजता और एआई नियंत्रण से जुड़े बड़े कानूनी मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है।

इकरा हसन के समर्थन में उतरे अखिलेश बोले- गुनाह तो बताइए?

सहारनपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। सांसद इकरा हसन ने पुलिस प्रशासन पर जबरन थाने में बिठाने और हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन जसाला गांव की एक बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) से मिलने पहुंची थीं। महिला के बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और वे इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थीं। सांसद का आरोप है कि पीड़ित पक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया। जब वे कार्यालय के बाहर पार्किंग एरिया में दूसरी अर्जी तैयार कर रही थीं, तभी भारी पुलिस बल ने वहां पहुंचकर उन पर ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा डालने का आरोप लगाया। इकरा हसन के अनुसार, उन्हें और उनके साथियों को गाड़ी में बिठाकर महिला पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां करीब 10 मिनट तक हिरासत में रखने के बाद उन्हें रिहा किया गया। सांसद ने ट्रैफिक बाधित करने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके पास गाड़ी सही जगह पार्क होने के वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं।

इस घटना के बाद मामला तब और बढ़ गया जब शांति भंग करने के आरोप में पूर्व राज्य मंत्री मेंगेराम कश्यप सहित पांच सपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही इकरा हसन तुरंत सदर बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचीं और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गईं। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। सांसद के समर्थन में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जिसके चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब किसी को सिर्फ न्याय के लिए आवाज उठाने की वजह से हिरासत में ले लिया जाता है, तो वही पल कलियुग होता है। उन्होंने पूछा कि पार्टी की सांसद का अपराध बस इतना था कि वह उस मां की मदद कर रही थीं जिसने अपना बेटा खो दिया है और जो इस संवेदनहीन शासन में न्याय के लिए भटक रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह की तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। फिलहाल, थाने के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है।

निर्मला सीतारमण पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज... कहां थीं मैम?

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा तंज कस दिया है। उन्होंने वित्त मंत्री से सीधे सवाल किया कि जब देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही थी, तब वह कहां थीं। शिवसेना यूबीटी नेता चतुर्वेदी का बयान सीतारमण के उस ट्वीट के जवाब में आया है, जिसमें वित्त मंत्री ने मोदी सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया था।

शिवसेना यूबीटी नेता चतुर्वेदी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हालेलुया! हमारी वित्त मंत्री वापस आ गई हैं! देश जानना चाहता था कि जब डॉलर मजबूत हो रहा था (ध्यान दें, मैंने यह नहीं कहा कि रुपया कमजोर हो रहा था), जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और संस्थागत विदेशी निवेशक (एफआईआई) नदारद थे, जब शेयर बाजार धराशायी हो रहा था और सोना-चांदी खरीदना मना हो गया था, तब मैम कहां थीं?

यह तंज वित्त मंत्री सीतारमण के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 से सरकार अपनी नीतियों से समाज के हर वर्ग किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और एमएसएमई की सेवा कर रही है, और वे उनके शासन ढांचे के मूल केंद्र में हैं।

इस दौरान सीतारमण ने कांग्रेस से पूछा था कि क्या 58 करोड़ जनधन खाते, 57 करोड़ मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, ई-श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम (जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार देता है), आयुष्मान भारत, 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान संवितरण, लखपति दीदी/ड्रोन दीदी योजनाएँ और ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे कदम अडानी/अंबानी के लिए हैं या गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए।

उन्होंने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 1 करोड़ स्वनिधि खाते, उर्वरकों पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ किसानों पर न डालने, एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस 5.0, कृषि ऋण वृद्धि और एमएसएमई ऋण वृद्धि जैसे कदमों का भी हवाला दिया, यह दर्शाने के लिए कि मोदी सरकार का ध्यान समाज के वंचित और मध्यम वर्गों पर केंद्रित है। यह राजनीतिक बयानबाजी आगामी चुनावों से पहले एक-दूसरे पर निशाना साधने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है।

पीएम मोदी की तारीफ कर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने विपक्ष में डाली फूट?

नई दिल्ली (एजेंसी)। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गुट के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का समर्थन कर कहा है कि राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर देश के सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, पीएम मोदी की विदेशी यात्राओं की कड़ी आलोचना कर रही हैं, लेकिन पवार के बयान से विपक्ष की एकता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम में पवार ने स्पष्ट किया कि भले ही उनके राजनीतिक विचार अलग हों, लेकिन जब देश के बाहर भारत की प्रतिष्ठा की बात होती है, तब सभी को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश के सम्मान की बात आती है, तब राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय हित में काम करने के मौके पर दलों को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साझा उद्देश्य के साथ आना चाहिए। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) गुट के प्रमुख पवार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने नेतृत्व में देश के भविष्य और प्रतिष्ठा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी यह टिप्पणी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की चल रही पांच देशों की यात्रा की आलोचना करने के तुरंत बाद आई है। राहुल गांधी ने कहा था कि इस संकट के समय में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से विदेश यात्रा न करने की अपील कर रहे हैं, जबकि वे स्वयं दुनिया घूम रहे हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दिए गए बयान ने निश्चित रूप से समूचे विपक्ष की एकजुटता और साझा रणनीति पर नए सिरे से चर्चा छेड़ दी है, खासकर तब जब आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्षी मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है।

डिटेक्शन और डिलीशन का काम हो चुका पूरा अब डिपोर्टेशन का होगा शुरू

-बंगाल में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर सीएम अधिकारी बोले

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल से कथित अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट से डिटेक्शन और डिलीशन का काम पहले ही हो चुका है और डिपोर्टेशन जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने देरी की थी। शुभेंधु ने कहा कि पहले हमने वोटर लिस्ट में अवैध निवासियों का पता लगाया, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटा दिया और अब उन्हें देश से निकालने का समय आ गया है। हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि मैं डरने वाला, झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरुरत नहीं है। बीजेपी ने जो कमिटमेंट दिया है, वो पूरा करने का काम बीजेपी का सीएम करेगा। राष्ट्र प्रथम है, देश को सुरक्षित रखने का काम बीजेपी करेगी। सीएम अधिकारी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे सीएम बनने से यहां टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस तनाव में हैं और अशांति पैदा कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा तनाव और परेशानी बांग्लादेश के लोगों, विशेषकर वहां के जमात संगठन को हो रही है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे डराने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के लिए देश पहले है और भाजपा इस देश को पूरी तरह ठीक करने का काम करेगी।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्होंने म्युनिसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर को चार विशिष्ट नाम दिए हैं, जिन्होंने बंगाल को जमकर लूटा है। उन्होंने इन चारों व्यक्तियों की कुल संपत्ति का विवरण मांगते हुए उनके खिलाफ कानूनी जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम अधिकारी ने पार्क सर्कस में पुलिस पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के किए गए अवैध निर्माणों जैसी अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस पर पत्थर फेंकने की हिम्मत करेगा, तो बीजेपी उसे उचित सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर न्याय का भरोसा दिया। अधिकारी ने ऐलान किया है कि आरजी कर अस्पताल से लेकर कामदुनी, पार्क स्ट्रीट, कस्बा लॉ कॉलेज और बोगतुई तक महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार के हर एक मामले की कड़ी कानूनी जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

ममता बनर्जी का बड़ा दावा : दिल्ली की सत्ता से जल्द हटेगी भाजपा सरकार

-बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ आंदोलन चलाने का किया ऐलान

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कालीघाट स्थित अपने आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटा दिया जाएगा। राज्य के हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है, जिसके साथ ही राज्य में पिछले 15 सालों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया है। इस हार के बाद भी टीएमसी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में नई सरकार के आने के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले हॉकर्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तथाकथित तानाशाही और बुलडोजर संस्कृति के कारण जनता में रोष बढ़ेगा, जो अंततः केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। इसके विरोध में टीएमसी ने कोलकाता, बालीगंज, हावड़ा जंक्शन और सियालदह रेलवे स्टेशन के आसपास बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। उन्हें उम्मीद है कि यह जन-आंदोलन भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी माहौल तैयार करेगा।

बैठक में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी वर्तमान मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला। उन्होंने साफ किया कि केंद्रीय एजेंसियों के नोटिस या दंडात्मक कार्रवाइयों के आगे वे झुकने वाले नहीं हैं और भाजपा के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।

दूसरी तरफ, चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के कई हिस्सों से हिंसा, आगजनी और झड़पों की खबरें आई हैं। इस मामले में टीएमसी ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी खुद वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुईं। उन्होंने अदालत से मांग की है कि प्रभावित कार्यकर्ताओं को तुरंत सुरक्षा दी जाए और इस पूरी हिंसा की कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए। उल्लेखनीय है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बनाई है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई है। इस राजनीतिक उलटफेर के बाद राज्य में माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है।

अल-नीनो ने दिखाया असर तो मानसून होगा कमजोर, मंडरा रहा खतरा

-चावल और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। महंगाई, गर्मी और मौसम की मार झेल रहे लोगों के सामने अब एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल अल-नीनो का असर भारतीय मानसून को कमजोर कर सकता है, जिससे चावल और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति चिंताजनक हो सकती है, जहां बड़ी आबादी का मुख्य भोजन चावल है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है कि अल-नीनो वाले सालों में देश के कई जिलों में खरीफ फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आई थी। अध्ययन के मुताबिक पिछले अल-नीनो वर्षों के दौरान 77 जिलों में चावल का उत्पादन 10 फीसदी से ज्यादा घट गया था। वहीं मक्का उत्पादन भी 65 जिलों में गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। इसके अलावा ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की पैदावार में भी कई जिलों में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

शोधकर्ताओं के मुताबिक अल-नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है और बारिश कम होती है। मानसून कमजोर होने से खरीफ सीजन की खेती प्रभावित होती है, जिससे धान, मक्का और अन्य फसलों का उत्पादन घट जाता है। यह अध्ययन 2023 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 2002, 2004 और 2009 जैसे प्रमुख अल-नीनो वर्षों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन में पाया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कई जिलों में धान की पैदावार में उल्लेखनीय कमी आई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इस साल भी अल-नीनो का प्रभाव रहा तो खरीफ फसलों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसी बीच उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि आने वाले दिनों में इसके 45 डिग्री तक जाने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे हालात में यदि मानसून कमजोर रहता है तो खेती और जल संसाधनों दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। आईसीएआर के कृषि भौतिकी विभाग से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि सरकार को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। सूखा सहन करने वाली फसल किस्मों को बढ़ावा देना, किसानों को मौसम आधारित सलाह उपलब्ध कराना, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करना और जिला स्तर पर वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करना बेहद जरूरी होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अल-नीनो जैसी घटनाएं अब ज्यादा देखने को मिल रही हैं, इसलिए पारंपरिक खेती पद्धतियों में बदलाव समय की मांग बन चुका है। किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि यदि समय पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो धान की बुवाई और उत्पादन दोनों प्रभावित होंगे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717